



Research Article

ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण

रूप सिंह

शोधकर्ता, जेएनवीयू जोधपुर, अतिरिक्त विकास अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * रूप सिंह

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22793251>

सारांश

ग्रामीण विकास भारत के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार, आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करना है। प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण विकास की अवधारणा, आवश्यकता तथा भारत में समय-समय पर अपनाए गए विभिन्न विकास दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में क्षेत्रीय दृष्टिकोण, बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण, लक्ष्य समूह दृष्टिकोण, मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण तथा रोजगारोन्मुख एकीकृत दृष्टिकोण को प्रमुख रूप से विवेचित किया गया है। इन दृष्टिकोणों के माध्यम से कृषि उत्पादकता, ग्रामीण रोजगार, गरीबी उन्मूलन, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि ग्रामीण विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और मानव संसाधन विकास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत तथा विशेष रूप से राजस्थान के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग आज भी कृषि, श्रम एवं सीमित संसाधनों पर निर्भर है। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सतत एवं समावेशी विकास के लिए कृषि के आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर पहुंच तथा वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार प्रभावी ग्रामीण विकास न केवल ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और संतुलित सामाजिक विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 10-08-2026
- Accepted: 13-09-2026
- Published: 16-09-2026
- IJCRM:5(5); 2026: 246-249
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

सिंह रूप. ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण.
Int J Contemp Res Multidiscip.
2026;5(5):246-249.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: ग्रामीण विकास, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि विकास, ग्रामीण रोजगार, गरीबी उन्मूलन, आधारभूत सुविधाएं, सतत विकास।

1. प्रस्तावना

ग्रामीण विकास एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है जिसमें ग्रामीण सामाजिक प्रणाली में नए विचार प्रस्तावित कर आधुनिक उत्पादन विधि और उचित सामयिक संगठन से प्रति व्यक्ति अधिक आय हो और उसका उच्च जीवन स्तर हो, क्योंकि ग्रामीण विकास आर्थिक क्षेत्र के सभी पहलुओं में अधिक उत्पादन प्राप्त करता है। इस उत्पादन को अधिकाधिक लोगों में इस प्रकार वितरण सुनिश्चित करता है जिससे वे जीवन की गुणवत्ता उत्पन्न कर सकें। इसके परिप्रेक्ष्य में जहां ग्रामीण विकास की आवश्यकता प्रतिपादित दी गई है, वहीं ग्रामीण विकास के प्रति कई दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, यथा- बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण, क्षेत्रीय दृष्टिकोण, लक्ष्य समूह दृष्टिकोण, मूलभूत दृष्टिकोण, रोजगारोन्मुख एकीकृत दृष्टिकोण आदि। इस क्रम में यह विशेषज्ञ ध्येय वाक्य रखा गया है कि अर्थ व्यवस्था के समस्त क्षेत्र एक ही अनुपात में विकास करेंगे, जिसमें उपभोग, विनियोग, एवं वेतन समान दर से बढ़ सकें। 1

ग्रामीण विकास के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई दृष्टिकोण नहीं है। यह ऐसा विकल्प है जो समय, स्थान और संस्कृति से प्रभावित होता है। ग्रामीण विकास एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई पक्ष, यथा- कृषि, लघु उद्योग, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, सामुदायिक संसाधन और सुविधाएं तथा ग्रामीण व्यक्तियों के रहने की स्थिति है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है श 2 जबकि इस संबंध में किए गए अनुसंधान संकेत करते हैं कि किसान और खेतिहर श्रमिक वंचित अवस्था में है और स्वयं के जीवन यापन में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने वाली आधुनिक और अभिनव रणनीतियों तथा विधियों के संदर्भ में उनमें जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास के इन दृष्टिकोणों का मुख्य उद्देश्य प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना है। वर्ष 1951 के बाद से, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ ही ये दृष्टिकोण अपनाए गए।

क्षेत्रीय दृष्टिकोण:-

ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय दृष्टिकोण का प्रमुख ध्येय तुलनात्मक लाभ के क्षेत्रों में एकाग्रता के साथ चयनित क्षेत्रों के गहन विकास को बढ़ावा देना था। देश में 1960 के दशक तक खाद्य मोर्चे, पर स्थिति बहुत गंभीर थी। ऐसे में खाद्य उत्पादन के लिए अधिक एकाग्रता की आवश्यकता से संभावित क्षेत्रों, संपन्न क्षेत्रों तथा उच्च कृषि उत्पादन में सक्षम क्षेत्रों का पता लगाने की रणनीति का प्रारूप तैयार हुआ, तब रकबे के विस्तार के स्थान पर प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, साथ ही वर्ष 1960 में गहन कृषि विकास कार्यक्रम और 1963 में गहन कृषि क्षेत्र कार्य शुरू किए गए जो कृषि विकास में मानक थे जिनसे कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, कारण कि दोनों में ग्रामीण परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव के साथ गुणात्मक रूप से भिन्न आधार पर कृषि पर जोर दिया गया था। इसी क्रम में कृषि से कामगारों की मुक्ति और कृषि वाणिज्यीकरण के प्रयास शुरू किए गए। इसके लिए यह श्लोक आधार बना-

यथा शूद्र जनप्राय, समृद्ध कृषि कला, क्षेत्रोप योग भूमहर्ष, वसति ग्राम संशिका। 3

बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण

बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण का प्रमुख उद्देश्य स्व-सहायता और आत्म निर्भरता के आधार पर गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। इसे ग्रामीण विकास के क्रम में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना गया क्योंकि इसी से ग्रामीण भारत के उत्थान की नींव पड़ी। सन् 1900 के दशक के प्रारंभ में ग्रामीण विकास के प्रयास बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण के साथ शुरू हुए जिसमें कृषि, पशु पालन, सहकारिता, सिंचाई, एवं लघु उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, आवास, परिवहन और संचार, कल्याण से संबंधित गतिविधियों तथा महिला- शिशु देखभाल एवं ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सम्मिलित है। सन् 1962 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत थे। इस दृष्टिकोण का आधार यह मत रहा कि निर्धनों के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से उनके जीवन स्तर में सुधार हो तथा इसके लिए पूंजी एवं तकनीक का अच्छा उपयोग हो। इस में गरीबों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। 4

लक्ष्य समूह दृष्टिकोण

समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मध्य सामाजिक न्याय के साथ विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य लक्ष्य समूह दृष्टिकोण का है। पिछड़े क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की फिर से परिकल्पना की गई। सीमांत और छोटे किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए लघु किसान विकास अभिकरण और सीमांत किसान विकास अभिकरण शुरू, किए गए। लक्ष्य समूह दृष्टिकोण के बेहतर परिणाम मिले तथा सूचना और सुविधाएं संतोषजनक व पर्याप्त रही। इसमें सामाजिक आर्थिक दशा को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को सार्थक बनाने के कम में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना प्रमुख कार्य रहा। 5

मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण:-

मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण विकास योजना के लिए मुख्य चिंतन के रूप में गरीबी से ग्रसित लोगों के जीवन स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति को वरीयता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक उपभोग की समानता है। इसीलिए यह विकास रणनीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसके उद्देश्य गरीबी तथा असमानता में कमी लाना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना तथा वितरणात्मक न्याय करना है। पांचवी योजना अवधि के पहले वर्ष के दौरान देश के अन्दर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 1974 में प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम मानव संसाधन में निवेश का कार्यक्रम है जिसके महत्वपूर्ण पक्षों में एक उत्पादक क्षमता बढ़ाना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें पेयजल, विद्युतीकरण, आवास, मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार, पोषण आदि है। इसके साथ ही ग्रामीणों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन को भी समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया। 6

रोजगारोन्मुख एकीकृत दृष्टिकोण:-

क्षेत्रीय और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना रोजगारोन्मुख एकीकृत दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य था। पूर्व के दृष्टिकोण की सीमाओं पर नियंत्रण पाने और

ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 1978-79 में प्रारंभ किया गया एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण पर आधारित था। इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास की बहु-खंड अवधारणा के साथ व्यक्तियों, एक बहु-क्षेत्र, बहु-स्तर की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत और भी कई कार्यक्रम शुरू किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य वंचितों का त्वरित कल्याण और प्रगति सुनिश्चित करना था, साथ ही ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर रहा। इसमें ग्रामीण निर्धनता पर प्रत्यक्ष प्रहार करते हुए परिसम्पत्तियों के सृजन और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनतम लोगों तक पहुंचने के प्रयत्न करना प्रमुख कार्य था। 7

ग्रामीण विकास की आवश्यकता:-

ग्रामीण विकास किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत जैसे विशाल तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए तो और भी आवश्यक हो जाता है, कारण कि भारत के अधिसंख्य लोग गांवों में निवास करते हैं। ग्रामीण भारत को ही भारतीयता की पहचान माना गया है तथा समृद्ध गांव ही समृद्ध भारत की पृष्ठभूमि है। देश का सर्वांगीण विकास ग्रामीण विकास से ही संभव है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब, 21 करोड़, 1 लाख, 93 हजार 422 थी जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 83 करोड़, 30 लाख, 87 हजार 622 थी अर्थात् देश के 68.84 प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे।

राजस्थान का संदर्भ लें तो राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़, 86 लाख 21 हजार 12 थी जिसमें से ग्रामीण आबादी 5 करोड़ 15 लाख 40 हजार 236 थी, अर्थात् राज्य की कुल जनसंख्या का 75.10 प्रतिशत भाग ग्रामीण था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत 6 लाख 40 हजार 867 गांव थे। 8

ग्रामीण विकास वर्तमान जीवन की आवश्यकता ही नहीं है, अपितु अपरिहार्य है क्योंकि स्वाधीनता के सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी भारत के गांव अब तक अपेक्षित है। निर्धनता एवं अशिक्षा ऐसे कारक हैं जो ग्रामीण विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया को बाधित किए हुए हैं। ग्रामीण विकास इसलिए भी आवश्यक है कि सदियों से ग्रामीण समुदाय विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला समुदाय कुप्रथाओं, अंधविश्वासों तथा सामाजिक रुढ़िवादी और कुरीतियों से जकड़ा हुआ है इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी आवश्यक है जिससे ग्रामीण समुदाय राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान कर सके और यह तभी संभव है जब गांवों में विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सशक्त, प्रभावी और सार्थक रूप से हों। यह भी इस क्रम में ध्यान देने योग्य बात है कि विकास का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। श७ समूहों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार ग्रामीण विकास के माध्यम से ही संभव है।

ग्रामीण विकास की आवश्यकता देश में निर्धनता तथा बेरोजगारी कम करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली, स्वच्छ जल, जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि में तो आवश्यक है ही, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने,

ग्रामीण आय बढ़ाने तथा शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए भी आवश्यक है। ग्रामीण विकास की आवश्यकता इन आधारों पर है, यथा:-

आर्थिक विकास:- यह ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को कम करता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, यह कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करता है।

बुनियादी सुविधाओं का विकास:- यह गांवों में बेहतर सड़कों, स्वच्छ पेयजल, बिजली, परिवहन, संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं की सुलभता के लिए ढांचे का निर्माण करता है, स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करता है जिससे मानव संसाधन का विकास होता है।

जीवन स्तर में सुधार:- यह ग्रामीण जन संख्या को पर्याप्त भोजन, स्वच्छ वातावरण, आवास और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में मदद करता है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है और सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है।

नगरीकरण पर नियंत्रण:- यह शहरी क्षेत्रों पर अत्यधिक दबाव को कम करता है जो बहुधा भीड़भाड़, प्रदूषण और आवास की कमी आदि समस्याओं से ग्रसित होते हैं, यह नगरों की तरफ होने वाले ग्रामीण लोगों के पलायन को कम कर सकता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बना सकता है।

कृषि का आधुनिकीकरण:- भारतीय ग्राम्य जीवन का मुख्य आधार कृषि प्राचीन काल से ही रहा है जिसके आधुनिकीकरण में ग्रामीण विकास सहायक हो सकता है अतएव इसलिए भी आवश्यकता है। कृषि पर निर्भर अधिसंख्य लोगों के लिए ग्रामीण विकास कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद, बीज और उपकरण उपलब्ध कराने, किसानों को कर्ज सुलभ कराने आदि के साथ ही कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी के समावेश करने में सहायक हो सकता है।

ग्रामीण विकास की आवश्यकता विश्व बैंक के प्रकाशित ग्रामीण विकास परिपत्र से प्रतिपादित हो जाती है जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण विकास एक रणनीति है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में एक विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए है। यह श्रेणी ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों की है जिसमें छोटे किसान, भूमिहीन तथा महिलाएं प्रमुख हैं। अगर विकास इस श्रेणी को नहीं छू पाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ग्रामीण विकास इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह एक लचीली संकल्पना है जिसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है। इसमें कृषि विकास, सामाजिक-आर्थिक संरचना, उचित मजदूरी, भूमिहीनों को भूमि एवं आवास, ग्रामीण नियोजन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, संप्रेषण इत्यादि शामिल है, अतएव इसे एक आन्दोलन के रूप में अपनाने की भी आवश्यकता है। 11

संदर्भ सूची

1. घोष अलघ. New Horizons in Planning. California: World Press Pvt Ltd; 1956. p. 12.
2. अग्रवाल एस. पूर्व-पश्चिम ग्रामीण विकास. अध्याय 5: ग्रामीण विकास. International Journal of Socio-Legal Analysis and Rural Development. 2019.
3. दास गौड़ राम. हमारे गांव की कहानी. नई दिल्ली: सस्ता साहित्य मंडल; 1938. p. 2.
4. पार्थ सारथी जी. Integrated Rural Development: Concept, Theoretical Basis and Contrast in Rural

- Development in India. नई दिल्ली: Agricultural Publishers; 1981. p. 25.
5. नारायण इकबाल. Panchayati Raj Administration in Rajasthan. आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल; 1973. p. 62.
 6. जाट सावरलाल, शर्मा प्रकाश. ग्रामीण विकास: एक अध्ययन. जयपुर: Sublime Publications; 1991. p. 6.
 7. कुरुक्षेत्र. नवंबर 1994. p. 13.
 8. कटारिया सुरेन्द्र. भारतीय लोक प्रशासन. जयपुर: National Publishing House; 2012. p. 64.
 9. ठाकुर BN. Sociology for Rural Development. नई दिल्ली: Classical Publishing Company; 1988. p. 89.
 10. माहेश्वरी SR. Rural Development in India. नई दिल्ली: क्षेत्र Publications; 1985. p. 18.
 11. सिंह होशियार. Approaches to Rural Development in Evaluative Survey in India. जयपुर: Printwell Publishers; 1985. p. 9.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author



रूप सिंह शोधकर्ता हैं तथा जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध हैं। वे जिला परिषद, जोधपुर, राजस्थान में अतिरिक्त विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनका शोध एवं व्यावसायिक अनुभव ग्रामीण विकास, प्रशासन, विकास योजनाओं तथा स्थानीय शासन से संबंधित विषयों में रुचि और व्यावहारिक समझ को दर्शाता है।